Hkkjrh; turk ikVh

(केंद्रीय कार्यालय)

11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 25 फरवरी, 2010

नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) श्री अरूण जेटली द्वारा मूल्यवृद्धि पर की गई बहस के मुख्य बिंदु

महोदय,

आदर्श स्थिति यह होती कि हम एक ऐसे प्रस्ताव के तहत बहस करते, जिसमें मतदान का प्रावधान होता। संसद को बहस की सीमाओं से दूर जाना चाहिए। देश में मूल्य स्थिति को सुलझाने के बारे में सरकार को संसदीय मत संग्रह कराना चाहिए। किंतु क्योंकि सरकार ऐसा करने की अनिच्छुक है अतः मूल्यवृद्धि से जूझने में सरकार की संवेदनाहीनता तथा अक्षमता को उजागर करने के लिए हम सदन के मंच का उपयोग करना चाहते है।

सरकार आर्थिक प्रबंधन के बारे में गंभीर नहीं है। कल का रेल बजट जो इस सत्र के अर्थ संबंधी कार्यकलाप में से सर्वप्रथम है उससे देश को केवल हास्यास्पद राहत पहुँची है। रेलमंत्री स्पोर्ट स्टेडियम, मिनरल वाटर बोटलिंग प्लांट, मेडिकल संस्थाओं और भारत–बांग्लादेश संबंधों आदि के बारे में चिंतित थीं न कि अपने मूल कार्यकलाप के बारे में। मुझे टाटा स्टील का वह प्रोमो याद आता है, जिसमें कहा गया था, "हम भी इस्पात निर्मित करते है"। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस स्थिति से जूझने में असहाय हो गया है ? 'कांग्रेस संदेश' के संपादकीय में एक स्वीकारात्मक वक्तव्य छपा है, जिसमें कहा गया है, "गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री कार्यालय तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां रहती है"। सदैव से ही मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मंत्रिमंडल अलग–अलग दिशाओं में जाकर काम नहीं कर सकता है। कोई भी सरकार इस आधार पर असहायता व्यक्त नहीं कर सकती है कि मंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पत्रिका 'राष्ट्रवादी' के संपादकीय में टिप्पणी की गई है कि यदि लोग चीनी नहीं खाते है तो वे मर या व्यथित नहीं हो जाएंगे। सत्ता में बैठे लोगों में ऐसी संवेदनहीनता है। उनकी तुलना Marie Antoinette की इस टिप्पणी से की जा सकती है – "यदि उन्हें रोटी नहीं मिलती है तो वे केक खाएं"।

सरकार का रवैया

इस सरकार का मूल्य स्थिति पर सामान्य रवैया घोर अनर्थकारी रहा है। क्या सरकार के पास इस बारे में कोई चिंतन नहीं बचा है अथवा इस स्थिति से कैसे निपटा जाए इस बारे में कोई विचार

नहीं बचा है ? क्या सरकार अपनी नाक से आगे नहीं देख सकती है तथा अभाव का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकती है कि उसे बाजार पर अंकुश रखने के लिए आयात या स्टॉक का सहारा लेना है ? क्या कोई नीतिगत हेरा–फेरी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि हुई है अथवा सरकार इस स्थिति से निपटने में असहाय महसूस कर रही है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ रही है ? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने कुछ न करने का और बाजार को स्वयं अपनी समस्या सुलझाने तक का इंतजार करने का रवैया अपना लिया है।

वास्तविक स्थिति

थोक मूल्य सूचकांक वास्तविक मूल्य स्थिति को अभिव्यक्त नहीं करता है। थोक मूल्य सूचकांक में 8.56 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की स्थिति दर्शायी गई है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 14.97 प्रतिशत और कृषि कर्मियों के लिए 17.41 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। खाद्य मूल्य सूचकांक 17 से लेकर 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हम अभी–अभी मंदी की स्थिति से उबरे हैं। क्रय शक्ति कमजोर है। Slow Down सामान्यतः मंदी की स्थिति अथवा मूल्यह्रास दर्शाता है। Downturn के दौरान भारत ने खाद्यमूल्य स्फीति देखी थी। हम निश्चित रूप से द्विअंकीय मुद्रास्फीति की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मुद्रास्फीति संप्रग सरकार द्वारा उपभोक्ता पर थोपा गया अनधिनियमित कर है। फुटकर दुकानों पर मूल्य मंडियों से कहीं अधिक हैं। वास्तविक मूल्य दर्शाता है कि दिसम्बर, 2009 में प्रसंस्करित खाद्य के मूल्य में 27 प्रतिशत की, आलू के मूल्य में 70 प्रतिशत की, प्याज के मूल्य में 45 प्रतिशत की, दाल के मूल्य में 45 प्रतिशत की तथा खाद्यान्नों आदि के मूल्यों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार वर्तमान दाल नीति के बारे में सचिन तेंदुलकर की नकल कर रही है। दाल मूल्यों ने शतक बना दिया है, चीनी के मूल्य पहले ही अर्धशतक बना चुके है। अधिक सक्रियता दिखाने और स्थिति से निपटने के बजाय सरकार झूठे बहाने ढूंढ रही है।

सूखा

सरकार का दावा है कि असमान मानसून के कारण खरीफ की फसल में 18 मिलियन टन की कमी आई है। यह अब तक मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। 2002 के सूखा के दौरान खाद्यान्नों में 40 मिलियन टन की कमी हुई थी। बाजार 60 मिलियन टन खाद्यान्नों से पटा पड़ा था और 2002–2003 में मुद्रास्फीति को 3.4 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। आज यह 2 अंकों में पहुंच गई है।

वायदा बाजार

अधिशेष की अर्थव्यवस्था में ही वायदा बाजार तथा वस्तु विनिमय का सहारा लिया गया था। क्या संप्रग सरकार को अभाव की अर्थव्यवस्था में इस नीति की पुनरीक्षा नहीं करनी चाहिए थी ? स्पष्टतः

केवल 1 प्रतिशत actual delivery के साथ वस्तु विनिमय पर यदि 4.5 लाख करोड़ का वायदा बाजार हो तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आशाएं पैदा हो जाएंगी।

राज्य सरकार

केन्द्र द्वारा राज्यों पर – विशेषतया प्रतिपक्ष द्वारा शासित राज्यों पर आरोप लगाना अनुचित होगा। जमाखोरी के विरूद्ध कुल जितनी भी सख्त छापेमारी की गई है उनमें से 83 प्रतिशत गैर–संप्रग शासित राज्यों में हुई हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह केवल 17 प्रतिशत हुई है। यह मुख्यमंत्रियों के सामने प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट हुआ था।

चीनी अर्थव्यवस्था

स्पष्टतः सरकार के चीनी मूल्य निर्धारण में मिल मालिकों की बात मानी गई है। राज्य परामर्शित मूल्यों को त्यागने की पूरी अवधारणा किसानों को नुकसान पहुंचाने और मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनाई गई थी। 49 लाख टन चीनी 12.50 रूपए प्रतिकिलो ग्राम की दर से निर्यात की गई थी, पर देश में चीनी 36 रूपए प्रतिकिलो ग्राम की दर पर आयात की गई है। 15–02–2010 को 10 हजार टन चीनी के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई, जबकि अर्थव्यवस्था अभाव का सामना कर रही है। गुजरात के बंदरगाहों पर पड़ी 9 लाख टन चीनी अभी भी उपभोक्ता के उपयोग के लिए प्रसंस्करित होने की प्रतीक्षा कर रही है ? चीनी के मूल्यों में वृद्धि नीति में हेरा–फेरी का परिणाम है।

मूल्यवृद्धि में न्यूनतम समर्थन मूल्य का इजाफा

सरकार ने बार–बार यह झूठा बहाना किया है कि संप्रग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यों में इजाफा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के पीछे यह आशय होता है कि उससे किसानों को उर्वरक लागत, परिवहन लागत, ईंधन मूल्य, बिजली लागत और निवर्हन लागत के विरूद्ध राहत मिल सके। कुछ फसलों को प्रोत्साहन देने का भी इसका आशय होता है। संक्षेप में इससे मूल्य बढ़ सकते है परंतु दीर्घावधि में कुछ फसलों के बुआई क्षेत्रों को बढ़ाकर अधिक उत्पादन मिलता है तथा कीमतें कम हो जाती है।

नरेगा के कारण उच्च उपभोग पैटर्न

इस देश में सदैव ही कार्य के बदले अनाज तथा अंत्योदय स्कीम के अधीन दुर्बल वर्ग को राशन का वितरण होता रहा है। इन इमदादों को भुखमरी दूर करने और दुर्बल वर्गों को खाने का अधिकार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। क्योंकि इन्हें अब नरेगा स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है इसलिए इनके परिणामस्वरूप अभाव नहीं हो सकता।

तेल के मूल्यों में वृद्धि

तेल के मूल्यों में वृद्धि को अभी उपभोक्ताओं पर नहीं लादा गया है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में इसके प्रभाव को महसूस नहीं किया गया है। स्पष्टतः इसके कारण मूल्यवृद्धि नहीं हुई है। फिर भी यदि अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य ऊंचे हो जाते है तो pricing revenue को neutral रखने के लिए duty components को युक्तियुक्त बनाना होगा। Excise duty, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क तेल के मूल्यों में आधे से अधिक योगदान करते हैं। यदि कर संरचना समान रहती है तो वैश्विक मूल्यों में प्रत्येक वृद्धि राज्य के राजस्व संग्रह को अनुचित रूप से बढ़ाती है। यदि राज्य ने revenue neutral policy अपनाई होती तो मूल्यों का प्रभाव समकृत हो सकता था।

थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक का सेवाओं तथा काफी अधिक संख्या में खाद्य वस्तुओं में असर नहीं होता है। इससे बाजार में मूल्यों की वास्तविक वृद्धि की जानकारी नहीं मिलती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता के अधिक निकट है। दोनों के बीच भारी अंतर है। विश्व के अधिकांश देशों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपना लिया है तथा थोक मूल्य सूचकांक को त्याग दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपभोक्ता भी कुछ काल्पनिक या अवास्तविक आंकड़ों के बजाय मूल्य वृद्धि के वास्तविक प्रभाव को महसूस करता है।

मूल्यों में नियंत्रण की सीमा से बाहर वृद्धि हुई है। सरकार आपूर्ति पक्ष के अभावों की पूर्व आशा करने में विफल रही है। सरकार उपभोक्ताओं को विशेषकर खाद्यों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करके भारी कष्ट पहुंचाती जा रही है। सरकार को शासन करने का मूल मंत्र सीखना चाहिए – कार्य करो या हट जाओ।

(रामकृपाल सिन्हा)
सचिव, भाजपा संसदीय दल